TITLE CODE:- UPHIN51504

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 225
दि. 16.12.2025,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

प्रधानमंत्री का जॉर्डन के अम्मान में विशेष स्वागत, पीएम डॉ. जाफर हसन ने गर्मजोशी से स्वागत किया

• प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अम्मान पहुंच गए हैं। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के प्रतीक के रूप में एक विशेष भाव के तहत, अम्मान हवाई अड्डे पर पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जॉर्डन के प्रधानमंत्री डॉ. जाफर हसन ने गर्मजोशी से स्वागत किया और समारोहपूर्वक उनका अभिवादन किया।

• यह जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की उनकी तीन देशों की यात्रा का पहला पड़ाव है। जॉर्डन की यह पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा 37 साल के अंतराल के बाद हो रही है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के साथ-साथ हो रही है।

• जॉर्डन के महामहिम राजा अब्दुल्ला द्वितीय के साथ बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ

(एजेंसी)।

मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने भारत और जॉर्डन के संबंधों को नए पायदान पर ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार रखें। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं।

इस वर्ष हम अपने राजनैतिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपुल टू पीपुल टाइस जैसे

क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे।

वैश्विक स्तर पर भी हम करीबी संपर्क में रहे हैं। गाजा पर शुरूआत से ही आपकी बहुत सक्रिय और सकारात्मक भूमिका रही है। हम सभी की आशा है कि इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। आतंकवाद के विरुद्ध हमारा साझा और स्पष्ट रुख है। आपके नेतृत्व में जॉर्डन ने आतंकवाद, उग्रवाद और रेडिकलाइजेशन के खिलाफ पूरी मानवता को एक सशक्त और रणनीतिक संदेश दिए हैं। रिस्ट्रिक्टेड मैटर के दौरान हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को और मजबूती देने पर चर्चा की। 2018 में आपकी भारत यात्रा के समय हमने इस्लामिक हैरिटेज पर एक कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। मुझे याद है कि हमारी पहली मुलाकात भी 2015 में वठ के साइडलाइन पर वायलेंट एक्समिज्म को काउंटर करने पर केंद्रित एक इवेंट पर हुई थी। आपने तब भी इस विषय पर इंस्पिरेशनल रिमार्क दिए थे। मॉडरेशन को बढ़ावा देने के लिए आपके प्रयास क्षेत्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम इस दिशा में मिलकर ठोस रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। हम आपसी सहयोग के अन्य सभी आयामों को और सशक्त बनाएंगे। एक बार फिर आपके आतिथ्य सत्कार के लिए मैं आपका और जॉर्डन के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

यूपी: सीएम योगी का नेहरू पर हमला- कहा देश में आतंकवाद और अलगाववाद की जड़ में हैं पूर्व पीएम

लखनऊ, (एजेंसी)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने जम्मू-कश्मीर को इतना विवादित करने का कार्य किया कि आजादी के बाद से वह लगातार भारत को डसता रहा। पंडित नेहरू के कारण उसी कश्मीर से देश को उग्रवाद, अलगाववाद प्राप्त हुआ था। देश पीएम नरेंद्र मोदी का आभारी है, जिन्होंने लौहपुरुष व डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए धारा-370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए एक देश में एक प्रधान,

एक विधान और एक निशान के संकल्प को आगे बढ़ाया।

योगी सोमवार को जीपीओ स्थित पार्क में लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का यशस्वी नेतृत्व और लंबे समय तक प्राप्त होता, लेकिन देश का दुर्भाग्य रहा कि 15 दिसंबर 1950 को उनका नश्वर शरीर जवाब दे गया। आजादी के बाद सरदार पटेल की सूझबूझ से जूनागढ़ और हैदराबाद की रिसायतें भारत का हिस्सा बनीं।

सरदार पटेल ने गृहमंत्री के रूप में सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार, तमाम विवादों के समाधान के लिए तंत्र विकसित करने और भारत की प्रशासनिक सेवा को वर्तमान स्वरूप देने का कार्य भी किया।

जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री का बयान

(एजेंसी)।

आज, मैं हाशमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन के, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया और सल्तनत ऑफ ओमान की तीन देशों की यात्रा पर जा रहा हूं, ये तीनों ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के व्यापक समकालीन द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ पुराने सभ्यतागत संबंध हैं।

सबसे पहले, मैं महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन के निमंत्रण पर जॉर्डन जाऊंगा। यह ऐतिहासिक यात्रा हमारे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे होने का प्रतीक होगी। अपनी यात्रा के दौरान, मैं महामहिम किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन, जॉर्डन के प्रधानमंत्री महामहिम श्री जाफर हसन के साथ विस्तृत चर्चा करूंगा और महामहिम क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय के साथ भी मुलाकात करूंगा। अम्मान में, मैं जीवंत भारतीय समुदाय से भी मिलूंगा, जिन्होंने भारत-जॉर्डन संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

अम्मान से, इथियोपिया के प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. अबी अहमद अली के निमंत्रण पर, मैं फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इथियोपिया की अपनी पहली यात्रा करूंगा। अदीस अबाबा अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी है। 2023 में, भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अदीस अबाबा में, मैं महामहिम डॉ. अबी अहमद अली के साथ विस्तार से बातचीत करूंगा और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा। मुझे संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का भी सौभाग्य मिलेगा, जहां मैं "लोकतंत्र की जननी" के रूप में भारत की यात्रा और भारत-इथियोपिया साझेदारी ग्लोबल साउथ के लिए क्या मूल्य ला सकती है, इस पर अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक हूं।

अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में, मैं सल्तनत ऑफ ओमान जाऊंगा। मेरी यह यात्रा भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने का प्रतीक होगी।

तीन देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज (15 दिसंबर, 2025) राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में ईरान, ब्रुनेई दारुस्सलाम और माइक्रोनेशिया के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए।

1 इस्लामी गणराज्य ईरान के राजदूत, डॉ. मोहम्मद फथली

2. ब्रुनेई दारुस्सलाम की उच्चायुक्त, श्रीमती सिटी अरनीफरिजा हाजी मोहम्मद जैनी

3. माइक्रोनेशिया संघीय राज्यों के राजदूत, श्री जॉन फ्रिट्ज

डॉ. जितेंद्र सिंह ने संसद में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025 पेश किया

■ विधेयक में भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिए नए कानूनी तंत्र का प्रस्ताव है और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 तथा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 को निरस्त किया गया है

(एजेंसी)।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज संसद में सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल, 2025 पेश किया, जो भारत के परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले कानूनी तंत्र को अपडेट करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक जिम्मेदारी अधिनियम, 2010 को रद्द करना और उन्हें भारत की वर्तमान एवं भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुरूप एक एकल, व्यापक कानून में परिवर्तित करना है।

विधेयक के साथ संलग्न उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण के अनुसार, निरंतर अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से भारत को परमाणु ईंधन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को जिम्मेदारी के साथ संचालित करने में सक्षम बनाया है। इस अनुभव के आधार पर, सरकार स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं डेटा केंद्रों और भविष्य के लिए तैयार अनुप्रयोगों जैसी उभरती आवश्यकताओं के लिए चौबीसों घंटे विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने की संभावना देखती है।

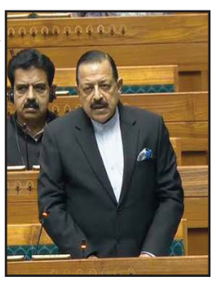

प्रस्तावित विधेयक भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा एवं जलवायु लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यह 2070 तक कार्बन न्यूनीकरण के लिए देश की रूपरेखा और 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य को रेखांकित करता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, विधेयक स्वदेशी परमाणु संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल देता है, साथ ही भारत को वैश्विक परमाणु ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में योगदानकर्ता के रूप में स्थापित करता है।

यह विधेयक परिचालन स्तर पर परमाणु ऊर्जा के उत्पादन या उपयोग में शामिल निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए लाइसेंस और सुरक्षा प्राधिकरण का प्रावधान करता है, साथ ही निलंबन या रद्द करने का स्पष्ट आधार भी बताता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, खाद्य एवं कृषि, उद्योग एवं अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में परमाणु और विकिरण प्रौद्योगिकियों के उपयोग को विनियमित करना है(जबकि अनुसंधान, विकास एवं नवाचार गतिविधियों को लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट प्रदान की गई है।

इस बिल में परमाणु क्षति के लिए एक संशोधित एवं व्यावहारिक नागरिक दायित्व तंत्र का भी प्रस्ताव है, यह परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड को वैधानिक स्थिति प्रदान करता है, और सुरक्षा, सुरक्षा उपाय, गुणवत्ता आश्वासन एवं आपातकालीन तैयारी से संबंधित तंत्र को मजबूत करता है। यह नए संस्थागत व्यवस्थाओं के निर्माण का प्रावधान करता है, जिसमें एक परमाणु ऊर्जा शिकायत सलाहकार परिषद का गठन, दावा अधिकारियों की नियुक्ति और गंभीर परमाणु क्षति से संबंधित मामलों के लिए एक परमाणु क्षति दावा आयोग शामिल हैं, जिसमें विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण अपीलीय प्राधिकरण के रूप में काम करेगा।

इस विधेयक पेश करके, सरकार ने संकेत दिया है कि वह भारत के ऊर्जा परिवर्तन, तकनीकी प्रगति एवं अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप नाभिकीय शासन को आधुनिक बनाने का सोच रखती है। प्रस्तावित कानून नाभिकीय ऊर्जा के विस्तार को सुरक्षा, जवाबदेही एवं सार्वजनिक हित के साथ संतुलित करने का प्रयास है, और नाभिकीय ऊर्जा को ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन उत्सर्जन वाले भविष्य की दिशा में राष्ट्रीय प्रयास को व्यापक बनाता है।

शोधन क्षमता, गैस पाइपलाइन नेटवर्क और परमाणु क्षेत्र में मौलिक विकास: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल

• दूरदर्शी सोच और अनवरत कार्य निष्पादन ने देश के ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति ला दी: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल

• ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव विश्वव्यापी पहुंच, सामर्थ्य, उपलब्धता, वित्तीय व्यवहार्यता और निरंतरता पर आधारित: श्री पीयूष गोयल

(एजेंसी)।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में एक ब्रीफिंग में बताया कि देश के ऊर्जा क्षेत्र की पिछले 11 वर्षों की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि दूरदर्शी सोच, ईमानदार इरादा और अनवरत कार्य निष्पादन किसी राष्ट्र की नियति को बदल सकता है।

सरदार वल्लभभाई पटेल की पुण्यतिथि पर श्री गोयल ने कहा कि राष्ट्र न केवल भारत के लौह पुरुष को याद कर रहा है, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति को भी याद करता है जो देश को राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना चाहता था।

श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की यही भावना साकार हुई है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश में 1,048 मिलियन टन कोयले का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया गया और कोयले के आयात में लगभग 8 प्रतिशत की कमी आई। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 11 वर्षों में देश की सौर ऊर्जा क्षमता 46 गुना बढ़ गई है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। पवन ऊर्जा क्षमता भी 2014 में 21 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 53 गीगावाट हो गई है। श्री गोयल ने आगे कहा कि अपना देश विश्व का चौथा सबसे बड़ा शोधन केंद्र बनकर उभरा है और अपनी शोधन क्षमता को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि 34,238 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 25,923 किलोमीटर चालू है। उन्होंने शांति विधेयक का भी उल्लेख किया, जिसका उद्देश्य निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भाग लेने की अनुमति देना है।

श्री गोयल ने कहा कि देश ने अतिरिक्त बिजली उत्पादन, ग्रिड एकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी की दिशा में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दृष्टिकोण और निरंतर प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने यह भी बताया कि देश ने बिजली की कमी से बिजली सुरक्षा की ओर और अब बिजली स्थिरता की ओर कदम बढ़ा दिया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशा-निर्देशन में 'सीएम डैशबोर्ड' के माध्यम से गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स (जीपीआई) की पहल

■ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के जीपीआई की समीक्षा बैठक

गांधीनगर, 15 दिसंबर : सरकार के विभिन्न विभाग राज्य के नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नागरिक केंद्रित योजनाओं, सेवाओं, विकासोन्मुखी कार्यों, इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तथा शिकायत निवारण के कामकाज से करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के दिशादर्शन में इस उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अलग अलग प्रकार के कामकाज के महत्वपूर्ण पैरामीटर्स को 'सीएम डैशबोर्ड' पर एक ही इंटीग्रेटड प्लेटफॉर्म पर लाया गया है।

देश में सुशासन के रोल मॉडल के रूप में स्थापित गुजरात में सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का दृष्टिकोण सुनिश्चित हो तथा योजनाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न विषयों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह

'सीएम डैशबोर्ड' कार्यरत किया गया है।

टेक्नोलॉजी के समुचित उपयोग की पहलरूपी में यह 'सीएम डैशबोर्ड' देश के अन्य राज्यों के लिए जन हितोन्मुखी व योजनागत कार्यों के मूल्यांकन तथा क्रियान्वयन के लिए एक उदाहरणरूपी प्लेटफॉर्म बना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुड गवर्नेंस की इस उज्ज्वल परंपरा को गतिपूर्वक आगे बढ़ाते हुए 'सीएम डैशबोर्ड' के माध्यम से समग्रोन्मुखी गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स (जीपीआई) तैयार करवाया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इस जीपीआई के संदर्भ में गांधीनगर में विभागों की कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव श्री एम. के. दास, मुख्यमंत्री श्री के मुख्य सलाहकार डॉ. हसमुख अढिया, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री एस. एस. राठौड, सरदार सरोवर नर्मदा निगम के अध्यक्ष श्री मुकेश पुरी, कृषि, ऊर्जा, नर्मदा जल संसाधन विभागों के अपर मुख्य सचिव, आदिजाति, श्रम एवं रोजगार विभाग के प्रधान सचिव तथा मुख्यमंत्री की अपर प्रधान सचिव श्रीमती अवंतिका सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सड़क एवं भवन विभाग के सचिव श्री प्रभात पटेलिया तथा अन्य संबंधित विभागों के सचिव भी सहभागी हुए।

सम्पादकीय

चुनाव सुधारों पर केंद्रित बहस

चुनाव सुधार पर सड़क से संसद तक चर्चा तेज हुई। शायद यह जरूरी भी था, क्योंकि पिछले कई दिनों से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे भी देश के 12 राज्यों व वेंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण तेज गति से हो रहा है पर यह भी देखने वाली बात है कि इस पर सियासत भी उसी स्पीड से चल रही है। लोकसभा में चुनाव सुधार के मुद्दे पर बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने इस चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी प्रकरण के जवाब में जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लिया और अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसने झूठ पैलाया है और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। अमित शाह ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मतदाता सूची का शुद्धिकरण है ताकि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हैं उनके नाम जुड़ जाएं, जो दो जगह मतदाता हैं उनके नाम कट जाएं और जो विदेशी नागरिक हैं उनको चुन-चुनकर हटाया जाए। उन्होंने कहा क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, यह घुसपैठिए तय करेंगे। एसआईआर से वुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। निर्णय करना पड़ेगा कि देश की संसद और विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं? इसके बाद राहुल गांधी खड़े हुए और अमित शाह से पूछा कि हिन्दुस्तान के इतिहास में चुनाव आयुक्तों को पूरी तरह माफी दी जाएगी, इसका जवाब दें। हरियाणा का एक उदाहरण इन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को दिया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। इस दौरान उन्होंने आरएसएस का नाम लिया। राहुल ने कहा कि समानता की भावना से आरएसएस को दिक्कत है। संघ ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें देखा और कहा कि चुनाव सुधार पर चर्चा कीजिए। नेता प्रतिपक्ष का मतलब ये नहीं कि वुछ भी बोलें। राहुल ने बहस की शुरूआत खादी से की। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक पैब्रिक की तरह ही है। कपड़ा कई धागों से बनता है। वैसे ही हमारा देश भी कई लोगों से मिलकर बनता है। देश के सारे धागे एक जैसे और अहम हैं। देश के सभी लोग बराबर हैं। राहुल ने कहा कि वोट के लिए देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सत्ता दल ने कब्जा कर लिया है।

ईसी, सीबीआई, ईडी सब पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग सत्ता के साथ मिला हुआ है। हमने इस बात के सुबूत दिए। सरकार इसी का इस्तेमाल कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयुक्त चुनने की प्रव्रिया को क्यों बदला गया। इस प्रव्रिया से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया? क्या सरकार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर विश्वास नहीं है? उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के इशारों पर चलती है। सत्ता पक्ष ही चुनाव आयोग को चला रहा है। राहुल ने ब्राजील की मॉडल का भी जिव्र किया। उन्होंने कहा कि ब्राजील की मॉडल का नाम 22 बार वोटर लिस्ट में आया। एक महिला का नाम 200 बार वोट लिस्ट में आया। चुनाव आयोग को सीसीटीवी पुटेज को वंट्रोल करने का मतलब क्या है और क्यों इस पुटेज को वुछ समय बाद हटाने का पैसला किया गया? पुटेज नष्ट करने की ताकत क्यों दी गईं? चुनाव आयुक्तों पर सजा का प्रवधान क्यों हटाया गया? हरियाणा चुनाव का जिव्र करते हुए राहुल ने कहा कि हरियाणा का चुनाव चोरी किया गया। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है तो उसे उठ रहे प्रश्नों का उत्तर प्रथमिकता से देना चाहिए।

पारदर्शिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर है। चुनाव आज से दो दशक पहले वैसे होते थे, इससे ज्यादा जरूरी है कि अब जो चुनाव हों प्रश्नों से पटे हों। लोकतंत्र के असली मालिक व रक्षक मतदाता हैं, जनता है और उसका चुनाव प्रव्रिया पर पूरा विश्वास होना चाहिए। यही भारत के लोकतंत्र की नींव हैं।

नई दिल्ली में 17 से 19 दिसंबर तक पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा

समग्र स्वास्थ्य और कल्याणकारी भविष्य को आकार देने के लिए वैश्विक नेता नई दिल्ली में एकत्रित होंगे

(एजेंसी)।

17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य और कल्याण पर वैश्विक संवाद का आयोजन किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा सह-आयोजित यह शिखर सम्मेलन संतुलित, समावेशी और सतत स्वास्थ्य प्रणालियों के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर के नीति निमार्ताओं, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, स्वदेशी ज्ञान धारकों और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाएगा।

इस शिखर सम्मेलन का विषय है ह्लसंतुलन की बहाली : स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यासह्व। वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों में असमानताओं, पर्यावरणीय तनाव और बढ़ती दीर्घकालिक बीमारियों के समय में यह शिखर सम्मेलन पारंपरिक चिकित्सा की प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करने के साथ-साथ विज्ञान, साक्ष्य और उत्तरदायित्वपूर्ण अभ्यास के आधार पर इसकी भूमिका को सुदृढ़ करेगा। 2023 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन से मिली सफलता आगे बढ़ाते हुए, नई दिल्ली में आयोजित यह सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडा में पारंपरिक चिकित्सा को स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025-2034 के मार्गदर्शन में आयोजित यह शिखर सम्मेलन इस बात पर केंद्रित होगा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियाँ जन-केंद्रित स्वास्थ्य सेवा और वैश्विक कल्याण में किस प्रकार सार्थक योगदान दे सकती हैं। इस दौरान उभरते साक्ष्यों, नवाचारों और नीतिगत मार्गों पर प्रकाश डाला जाएगा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों में पारंपरिक चिकित्सा के सुरक्षित, प्रभावी और नैतिक एकीकरण का समर्थन करते हैं।

शिखर सम्मेलन की तकनीकी चचाओं का शुभारंभ संतुलन बहाल करने पर एक उच्च स्तरीय पूर्ण सत्र से होगा, जिसमें ज्ञान, पहुंच, शासन और वैश्विक स्वास्थ्य में असंतुलन के कारणों की जांच पड़ताल की जाएगी और यह देखा जाएगा कि संतुलन बहाल करने का आज के समाजों के लिए क्या अर्थ हो सकता है। वैश्विक नेता और विशेषज्ञ इस बात पर विचार-विमर्श करेंगे कि वैज्ञानिक सटीकता, न्यायसंगत शासन, जैव विविधता संरक्षण, स्वदेशी अधिकार और विविध ज्ञान प्रणालियाँ मिलकर किस प्रकार एक अधिक न्यायसंगत और लचीले वैश्विक स्वास्थ्य भविष्य का निर्माण कर सकती हैं। सत्र में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति के कार्यान्वयन में सहयोग हेतु समन्वित वैश्विक कार्रवाई के लिए उभरते विचारों को भी प्रस्तुत किया जाएगा।

शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन विज्ञान और नवाचार पर विशेष बल दिया जाएगा। एक पूर्ण सत्र में पारंपरिक चिकित्सा में प्रगति लाने के लिए विज्ञान में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें गहन शोध, निरंतर वित्त पोषण, कार्य प्रणाली में सामंजस्य और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। चचाओं में इस बात पर बल दिया जाएगा कि सतत विकास और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में साक्ष्य-आधारित योगदानकर्ता के रूप में पारंपरिक चिकित्सा को सशक्त बनाने के लिए रणनीतिक निवेश और वैज्ञानिक सहयोग कितने आवश्यक हैं।

एक अन्य पूर्ण सत्र में संतुलन, सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों की पुनर्कल्पना पर

ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिसमें वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा रणनीति 2025-2034 की दृष्टि और प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। क्षेत्रीय और विभिन्न देशों के अनुभवों, विशेष रूप से दक्षिण- पूर्व एशिया और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के अनुभवों के आधार पर, यह सत्र प्रदर्शित करेगा कि नीतिगत, विधायी और नियामक प्रगति के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में कैसे एकीकृत किया जा रहा है। सुदृढ़ शासन ढांचे, गुणवत्ता आश्वासन और अंतर्राष्ट्रीय नियामक सहयोग का महत्व प्रमुख केंद्र बिंदु रहेगा।

यह शिखर सम्मेलन जवाबदेही, मानकों और आंकड़ों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा और यह पता लगाएगा कि पारंपरिक चिकित्सा में प्रगति को कैसे मापा और जिम्मेदारी से निर्देशित किया जा सकता है। एक समर्पित पूर्ण सत्र मानकीकृत आंकड़ों, पारदर्शी रिपोर्टिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित डिजिटल प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार, मानव- केंद्रित उपयोग की भूमिका की जांच करेगा। चचाओं में प्राचीन ज्ञान, सांस्कृतिक अखंडता और सामुदायिक विश्वास के प्रति सम्मान पर जोर दिया जाएगा, साथ ही ऐसे जवाबदेह ढांचे की मांग की जाएगी जो ज्ञान के अनेक तरीकों को मान्यता दें और संसाधनों के निष्पक्ष और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करें।

तीन दिनों तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में भविष्योन्मुखी मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के भीतर पारंपरिक चिकित्सा का विनियमन और एकीकरण; स्वदेशी लोगों के साथ ज्ञान का सम्मानजनक आदान-प्रदान; जैव विविधता का संरक्षण और औषधीय संसाधनों का सतत उपयोग; बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा और अनुसंधान, शिक्षा तथा व्यवहार में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदार अनुप्रयोग शामिल है।

इस कार्यक्रम में 25 से अधिक सत्रों में 170 से अधिक विशेषज्ञ वक्ता शामिल होंगे जो विज्ञान, नीति, व्यवहार और सामुदायिक नेतृत्व के दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करेंगे। 21 चयनित नवाचारों को प्रस्तुत किया जाएगा, जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से उभर रहे नए दृष्टिकोणों, उत्पादों और समाधानों पर प्रकाश डालेंगे। शिखर सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और जैव-सांस्कृतिक क्षेत्रों के अनुभवों को भी उजागर किया जाएगा, जो स्वास्थ्य, संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित करेगा।

इसमें सरकारी नेता, वैज्ञानिक, पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञ, आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि, उद्योग जगत के हितधारक और नागरिक समाज संगठन शामिल होंगे। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधित्व के साथ, यह शिखर सम्मेलन संवाद और सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगा। अपने समावेशी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, शिखर सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, जिससे नई दिल्ली में स्थल पर और ऑनलाइन, दोनों तरह से दुनिया भर के लोग इसमें भाग ले सकेंगे।

इस शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख परिणाम पारंपरिक चिकित्सा में साक्ष्य आधार, नीतिगत वातावरण और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से नई पहलों, सहयोगों, प्रतिज्ञाओं और प्रतिबद्धताओं की घोषणा होगी। इन परिणामों से स्वास्थ्य के प्रति अधिक समग्र, लचीले और टिकाऊ दृष्टिकोण विकसित होने की उम्मीद है, जो व्यापक वैश्विक स्वास्थ्य और विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप होंगे।

वर्ष 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के प्रथम वैश्विक शिखर सम्मेलन ने इस क्षेत्र में वैश्विक ध्यान, डेटा और प्रौद्योगिकियों को लाकर एक मजबूत नींव रखी। 2025 का शिखर सम्मेलन इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिक नवाचार, शासन और जवाबदेही का गहन अध्ययन करेगा साथ ही पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और उन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के महत्व पर भी बल देगा जिन पर वे निर्भर हैं।

विश्व ऐसे स्वास्थ्य समाधानों की तलाश कर रहा है जो न केवल प्रभावी हों बल्कि न्यायसंगत और टिकाऊ भी हों, ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। विभिन्न आवाजों और ज्ञान प्रणालियों को एक साथ लाकर, यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में व्यक्तियों, समुदायों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करने की दिशा में एक सामूहिक मार्ग प्रशस्त करने का लक्ष्य रखता है जब वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और कल्याण के भविष्य की पुनर्कल्पना की जा रही है।

'घरवाली पेड़वाली' ने मुंबई में निकाली भव्य और अनोखी बारात

यूपी। नए हल्के-फुल्के फैमिली कॉमेडी शो 'घरवाली पेडवाली' के लॉन्च से पहले प्रमोशन के लिए पहली बार मुंबई की सड़कों पर एक भव्य और अनोखी बारात निकाली, जिसने मुंबई को रंग, संगीत और मस्ती से भर दिया। शो के मुख्य किरदार जीतू पांडे (पारस अरोड़ा) अपनी दो दुल्हनों - सावी (सीरत कपूर) और लतिका (प्रियंवदा कांत) के साथ एक सजी-धजी रंगीन बस में सवार होकर शहर के कई मशहूर इलाकों से गुजरे। यह अनोखी बारात अंधेरी, जुहू, बांद्रा और वर्ली से होती हुई अमिताभ बच्चन के 'जलसा', शाहरुख खान के 'मन्नत', सलमान खान के 'गैलेक्सी अपार्टमेंट' और ईशा अंबानी के 'गुलिता' जैसे चर्चित ठिकानों के पास से गुजरी। रास्ते में बारात को देखने वाले लोगों की भारी भीड़ जुट गई। यहां बता दें

कि एण्डटीवी और जी5 पर 'घरवाली पेड़वाली' सोमवार से शुक्रवार, रात दस बजे प्रसारित है।

इस बारात में शो की पूरी ऑन-स्क्रीन फैमिली, रिश्तेदार और ऑफिस के किरदार नजर आए। इनमें शामिल थे- जीतू के माता-पिता गीता पांडे (गीता बिष्ट) और रीता पांडे (ऋचा सोनी), रमेश पांडे (हर्ष वशिष्ठ), सुरेश पांडे (बृज भूषण शुक्ला), दादाजी (बबलू मुखर्जी), रितिका बुआ (प्रीति सहाय दुबे), पनौती मामा (अमिताभ घाणेकर), सावित्री (प्रियंवदा सिंह), टिल्लूमल (सुदीप सारंगी), लट्टू (विनायक सिंह) और पप्पी (लोटा तिवारी)। इससे यह प्रमोशनल इवेंट बिल्कुल शो की तरह ही एक बड़े पारिवारिक जश्न में बदल गया।

बारात का सबसे खास पल बांद्रा बैंडस्टैंड पर देखने को मिला, जहां अचानक एक सरप्राइज फ्लैश मॉब शुरू हुआ। डांसर्स की जोशीली परफॉर्मेंस ने आम शाम को एक रंगीन उत्सव में बदल दिया। सड़क पर चलते लोग रुक गए, मोबाइल कैमरे चल पड़े और हर तरफ तालियों व मुस्कान की गूंज सुनाई दी। एक दूल्हा और दो दुल्हनों- जिसमें एक असली और दूसरी रहस्यमयी है- के दिलचस्प नजारे के साथ यह दृश्य शो की कहानी को बखूबी दर्शा रहा था। शो को टीवी स्क्रीन से बाहर निकालकर मुंबई की सड़कों तक ले जाना दर्शकों के लिए एक यादगार अनुभव बन गया, जिसने हर उम्र के लोगों का

नमामि कृष्णम ने नृत्य के जरिए कर्तव्य, सत्य और कर्म का महत्व बताया

लखनऊ भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अग्रणी सांस्कृतिक संस्था घृताक्षी संगीतशाला के तत्वावधान में आज शाम अंतरराष्ट्रीय बौद्ध संस्थान में आयोजित नमामि कृष्णम ने नृत्य के जरिए कर्तव्य, सत्य और कर्म का महत्व बताया। संगीत से सजे कार्यक्रम में मुस्कान खत्री के नृत्य निर्देशन में दिव्या, अरु, वंदिता सहित अन्य कलाकारों ने गुरूर ब्रह्मा गुरूर विष्णु पर भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत कर अपने गुरू के चरणों में अगाध श्रद्धा अर्पित की। गुरू नमन के उपरान्त रेयांशा, पूर्वी, मेधा, रश्मि, श्रद्धा, छवी,नीरज और आकृति ने नीर भरन कैसे जाऊं और मधुवन में राधिका नाची रे पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया।

कार्यक्रम के अगले सोपान में मुस्कान खत्री ने हे परमेश्वर पर अपनी

नृत्य प्रस्तुति से ईश्वर की महिमा का बखान किया। इसी प्रकार मृदुल और अक्षय लांबा ने कृष्ण-सुदामा चरित्र का भावाभिनय प्रस्तुत किया।मन को मोह लेने वाली इस पेशकश के उपरान्त घृताक्षी संगीतशाला के कलाकारों ने महाभारत लघु नृत्य नाटिका के जरिए भगवान श्री कृष्ण के बताये कर्तव्य, सत्य और कर्म का महत्व समझाया। हृदय को रोमांचित कर देने वाली इस प्रस्तुति के बाद चित्रांश अस्थाना, मनप्रीत, अर्थव, सूर्यांश, संदीप ने अपनी सुमधुर आवाज में राग यमन में निबद्ध सरस्वती वंदना की उत्कृष्ट प्रस्तुति दी।

इस मौके पर प्रो. मीरा दीक्षित, प्रमोद मिश्रा, जय किशन श्रीवास्तव, रोजी, शिवांगी और आलोक शर्मा को पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भेंट कर गुरू सम्मान से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सतेन्द्र आर्या, मुस्कान खत्री, पंडित आदित्य द्विवेदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

पूर्व सैनिकों का कल्याण और पुनर्वास

(एजेंसी)।

वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, पूर्व सैनिकों की संख्या 28,31,109 है। पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) ने पूर्व सैनिकों के लिए विभिन्न पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाएं चलाई हैं।

पुनर्वास महानिदेशालय की योजनाओं का विवरण

डीजीआर प्रायोजित सुरक्षा एजेंसी योजनाः डीजीआर, विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र के उपक्रमों को आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड प्रदान करने के लिए ईएसएम द्वारा संचालित निजी सुरक्षा एजेंसियों और राज्य ईएसएम निगमों को सूचीबद्ध/प्रायोजित करता है।

डीजीआर तकनीकी सेवा योजनाः डीजीआर सूचीबद्ध राज्य ईएसएम निगमों के माध्यम से सरकारी प्रतिष्ठानों/परिसरों में'तकनीकी सेवाओं' के लिए पूर्व सैनिकों की सेवाएं प्रदान करता है।

पूर्व सैनिक कोयला लदान एवं परिवहन योजना (केवल अधिकारियों के लिए): यह योजना कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और डीजीआर के बीच हुए समझौता ज्ञापन के आधार पर संचालित की जाती है। सीआईएल के वर्ष 2013 के समझौता ज्ञापन से हटने के बाद वर्तमान में यह योजना विचाराधीन है।

पूर्व सैनिक के लिए कोयला टिपर अटैचमेंट योजना (जेसीओ/ओआर के लिए): इस योजना को कोल लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन योजना से जोड़ा गया है।

विधवाओं और दिव्यांग सैनिकों के लिए टिपर अटैचमेंट योजनाः 65 वर्ष तक की आयु की विधवाएं और 50 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग सैनिक इस योजना के लिए नामांकन के पात्र हैं।

तेल विपणन कंपनियों के एलपीजी/खुदरा आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) वितरक पद के आवंटन हेतु 8 प्रतिशत आरक्षित कोटा के तहत डीजीआर पात्रता प्रमाण पत्र जारी करनाः युद्ध विधवाओं/युद्ध में शहीद हुए व्यक्तियों के आश्रितों, युद्ध के दौरान परिचालन क्षेत्र में सेवा के दौरान निशक्त हुए व्यक्तियों, सैन्य सेवा के कारण या उससे संबंधित कारणों से सेवारत रहते हुए शहीद हुए व्यक्तियों की विधवाओं/आश्रितों और सैन्य सेवा या उससे संबंधित कारणों से शांति काल में दिव्यांग हुए पूर्व सैनिकों सहित पूर्व सैनिक इस योजना के लिए पात्र हैं।

कंपनी के स्वामित्व वाले और कंपनी द्वारा संचालित (सीओसीओ) खुदरा दुकानों का प्रबंधनः इच्छुक पूर्व सैनिक अधिकारी और जेसीओ, जिन्होंने किसी अन्य सरकारी/डीजीआर योजना का लाभ नहीं उठाया है, को तेल कंपनी द्वारा आगे चयन के लिए अनुरोध के आधार पर सीओसीओ के लिए प्रायोजित किया जाता है।

एनसीआर/पुणे में सीएनजी स्टेशनों का प्रबंधनः इस योजना में पंजीकृत इच्छुक पूर्व सैनिकों को आईजीएल (नई दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र) और एमएनजीएल (पुणे/नासिक) से अनुरोध प्राप्त होने पर प्रायोजित किया जाता है।

एनसीआर में मदर डेयरी के दूध बूथ और फल एवं सब्जी (सफल) की दुकानों का आवंटनः पूर्व-शिक्षित वयस्कों (पूर्व सैनिकों) को 60 वर्ष की आयु तक दूध/सफल (फल एवं सब्जी) बूथों के लिए अलग से पंजीकृत किया जाता है। वे इन दुकानों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाते हैं।

पूर्व सैनिकों को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) में शामिल करनाः सरकार की पीएमबीजेपी योजना का उद्देश्य देशभर में जेनेरिक दवाओं की दुकान स्थापित करना है ताकि सभी को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। डीजीआर ने इस योजना की शुरूआत जून 2023 में की थी।

पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल विकास पाठ्यक्रमः भारतीय सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए पुनर्वास/कौशल विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने और संचालित करने की जिम्मेदारी डीजीआर के प्रशिक्षण निदेशालय की है ताकि सेवानिवृत्त कर्मियों के कौशल को नागरिक क्षेत्र में सुचारू रूप से उपयुक्त रोजगार के लिए बढ़ाया जा सके।

अधिकारियों के लिए - पाठ्यक्रम शुल्क का 60 प्रतिशत रक्षा मंत्रालय/डीजीआर द्वारा और 40 प्रतिशत प्रत्येक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से वहन किया जाता है। अधिकारियों की विधवाएं भी उपरोक्त पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

जेसीओ/ओआर और समकक्षों के लिए - पाठ्यक्रम शुल्क का शत-प्रतिशत भुगतान रक्षा मंत्रालय/डीजीआर द्वारा किया जाता है। जेसीओ/ओआर की विधवाएं डीजीआर द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

महानिदेशालय पुनर्वास रोजगार/स्वरोजगार योजनाओं से कुल 67,316 पूर्व सैनिकों को लाभ मिला है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, पुनर्वास महानिदेशालय के कौशल विकास कार्यक्रमों, प्रशिक्षणों और योजनाओं के अंतर्गत कुल 11,589 सेवानिवृत्त और पूर्व-सेवानिवृत्त अधिकारियों/जूनियर कमीशंड अधिकारियों/अन्य रैंकों को पुनर्वास प्रशिक्षण/कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान किए गए हैं। सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों को भी उपरोक्त विवरण के अनुसार रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा प्रशिक्षण और कौशल प्रदान किया जा रहा है।

संग्रहालयों, सांस्कृतिक स्थलों और प्रदर्शनियों की स्थापना और आधुनिकीकरण

वर्तमान में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में देश भर में बावन (52) पुरातात्विक स्थल संग्रहालय हैं। राज्यवार सूची अनुलग्नक झ 1 में संलग्न है।

एएसआई द्वारा विकसित नए संग्रहालयों, दीघाओं और अनुभवात्मक स्थलों की सूची अनुलग्नक झ क्क में संलग्न है।

केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक बजट आवंटन के अनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पूरे देश में मौजूदा पुरातात्विक स्थल संग्रहालयों का वार्षिक रखरखाव और समय-समय पर उन्नयन करता है।

इसके अतिरिक्त, संस्कृति मंत्रालय संग्रहालय अनुदान योजना संचालित करता है जिसके तहत नए संग्रहालयों की स्थापना/मौजूदा संग्रहालयों के विकास/संग्रहालयों के डिजिटलीकरण और केंद्र/राज्य सरकारों, सोसाइटियों, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्टों द्वारा प्रबंधित संग्रहालयों के पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शनियों, विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर सप्ताह, आईकॉम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस और अन्य राष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से सांस्कृतिक संस्थानों के साथ जनभागीदारी को बढ़ाया है। इनसे दृश्यता बढ़ती है, जनसंपर्क गतिविधियों को समर्थन मिलता है और राष्ट्र की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करते हुए व्यापक जनहित उत्पन्न होता है।

पुरातत्व संग्रहालय स्थलों की व्याख्या और प्राचीन वस्तुओं के सुरक्षित प्रदर्शन के केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे सांस्कृतिक पर्यटन के महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। वे क्षेत्रीय शिल्पों और व्यंजनों को बढ़ावा देने सहित स्थानीय रचनात्मक अर्थव्यवस्थाओं का भी समर्थन करते हैं, और परिणामस्वरूप संबंधित आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने में योगदान देते हैं।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले उत्सव

(एजेंसी)।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा देश भर में 362 सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए गए हैं। यह सभी केंद्र एक स्वायत्य संस्थान हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी क्षेत्रों को कवर करते हुए, सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा अपने सदस्य राज्यों में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों/उत्सवों में भाग लेने के लिए अन्य जोन/राज्यों के कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है। इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों ने महाकुंभ-2025, काशी तमिल संगमम, राष्ट्रीय एकता दिवस और वंदे भारतम कार्यक्रम आदि में भाग लिया। इन उत्सवों के माध्यम से दर्शकों और कला प्रेमियों को देश के अन्य क्षेत्रों की कलाओं और गीत, संगीत और नृत्यों का आनंद लेने और समझने का अवसर मिलता है। ये उत्सव हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियों को जानने और समझने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

साल 2024-25 के दौरान, देश में अलग-अलग सांस्कृतिक उत्सवों को आयोजित करने के लिए सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों को 11121.65 लाख रुपये आवंटित/जारी किए गए हैं।

सभी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों द्वारा अपने सदस्य राज्यों में आयोजित अलग-अलग सांस्कृतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों/त्योहारों में 55,519 कलाकारों/प्रस्तुतकताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से 2323 कलाकार/प्रस्तुतकर्ता ओडिशा के थे।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में दी।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गाजियाबाद और नोएडा की वायु प्रदूषण कार्य योजनाओं की उच्च-स्तरीय समीक्षा की अध्यक्षता की

दिल्ली-एनसीआर के लिए आगामी समीक्षा बैठकों की श्रृंखला

श्री भूपेंद्र यादव ने वायु गुणवत्ता नियंत्रण कार्य योजनाओं के जमीनी स्तर पर कड़ाई से कार्यान्वयन का आह्वान किया और अनुपालन न करने पर शून्य सहनशीलता का निर्देश दिया

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के विरूद्ध लड़ाई जीतने की कुंजी के रूप में जन भागीदारी पर जोर दिया गया

(एजेंसी)।

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने गाजियाबाद और नोएडा में वायु प्रदूषण से निपटने के उद्देश्य से बनाई गई कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। एनसीआर में शहर-विशिष्ट कार्य योजनाओं पर समीक्षा बैठकों की श्रृंखला के हिस्से के रूप में यह पहली समीक्षा थी, जिसका समापन आने वाले दिनों में राज्य-स्तरीय समीक्षा के साथ होगा। यह समीक्षा निर्धारित प्रारूप में की जा रही है, जैसा कि भूपेंद्र यादव ने 3 दिसंबर, 2025 को हुई पिछली समीक्षा बैठक में कहा था ताकि प्रगति का आकलन किया जा सके और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन को बेहतर किया जा सके।

दोनों शहरों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई पर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं। कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा निम्नलिखित प्रमुख मापदंडों के आधार पर की गई:

वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए स्मार्ट यातायात प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना;

औद्योगिक इकाइयों द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों का अनुपालन;

वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की स्थिति और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की उपलब्धता;

संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन प्रणाली और पार्किंग सुविधाओं को सुदृढ़ करना; निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट और नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू)/पुराने अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए ढांचागत संवर्धन; धूल को कम करने के लिए सड़कों का पूर्णतः पक्कीकरण/टाइलिंग करना; यांत्रिक सड़क सफाई मशीनों (एमआरएसएम) की तैनाती और एंटी-स्मॉग गन/वॉटर स्प्रिंकलर के उपयोग की स्थिति; पगडंडियों और खुले क्षेत्रों को हरा-भरा करना; जन भागीदारी पहल जिसमें सूचना एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां और ऐप आधारित शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं।

मंत्री महोदय ने शेष औद्योगिक इकाइयों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से अद्यतन जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्थापना के लिए किए जा रहे निरीक्षण और सहायता की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए 31 दिसंबर, 2025 की समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया और अनुपालन न करने वाली इकाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शहरी क्षेत्रों के आसपास के प्रदूषण फैलाने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों का निरीक्षण करने और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने का भी निर्देश दिया गया।

श्री यादव ने दिल्ली-एनसीआर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से अनुरोध किया कि वे शहर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाने वाले मापदंडों को और बेहतर बनाएं और आगामी दिनों में दिल्ली-एनसीआर की समग्र प्रगति की समीक्षा के लिए उन्हें संकलित करें। उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को धन का तर्कसंगत आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के मापदंडों को उन्नत करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री भूपेंद्र यादव ने कार्य योजनाओं और हरित गतिविधियों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन में जन प्रतिनिधियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर भी बल दिया ताकि प्रदूषण नियंत्रण एक सच्चा जनभागीदारी आंदोलन बन सके।

विशिष्ट सुझाव देते हुए, श्री भूपेंद्र यादव ने नगर निगम अधिकारियों को हरियाली बढ़ाने के प्रयासों के अंतर्गत गर्मी प्रतिरोधी और कम पानी की आवश्यकता वाली स्वदेशी किस्मों की झाड़ियों और घासों के रोपण हेतु संबंधित वन विभागों के साथ साझेदारी करने की सलाह दी। उन्होंने विभिन्न सरकारी और नगर निगम एजेंसियों के समन्वित प्रयासों के माध्यम से एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का भी आह्वान किया ताकि अलग-थलग दृष्टिकोण और संसाधनों के दोहराव से बचा जा सके। शहरी स्वच्छता और बेहतर शहरी नियोजन के लिए शहरी खुले स्थानों के उपयोग हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का अनुरोध किया गया।

श्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली-एनसीआर में लोकप्रिय मार्गों और प्रमुख यातायात गलियारों की पहचान करने के लिए एक अध्ययन करने का सुझाव दिया, जिसके बाद कम से कम इन प्रमुख मार्गों पर संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका कार्य योजनाएं न केवल वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप होनी चाहिए, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार होनी चाहिए, जिसमें बढ़ते हुए ठोस अपशिष्ट और निर्माण एवं विध्वंस कचरे के प्रसंस्करण के लिए शहरी स्थलों की अग्रिम पहचान शामिल हो।

बैठक में वायु गुणवर्त ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीएसपीसीबी) के प्रतिनिधि, जिला अधिकारी और नगर आयुक्त (गाजियाबाद) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नोएडा प्राधिकरण) उपस्थित थे।

भारतीय नौसेना उप प्रमुख की मालदीव यात्रा - अभ्यास एकता - 2025 का समापन

(एजेंसी)।

भारतीय नौसेना के उप प्रमुख, वाइस एडमिरल तरुण सोबती, 15 से 17 दिसंबर 2025 तक मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और मालदीव के बीच आयोजित संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 'एकता 2025' के समापन समारोह में भाग लेना है।

अभ्यास एकता, जिसकी शुरूआत 2017 में हुई थी, भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। इस अभ्यास के 8वें संस्करण में इंटरऑपरेबिलिटी और परिचालन तालमेल को बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक प्रोफेशनल बातचीत देखी गई। गतिविधियों में तकनीकी और कॉम्बैट डाइविंग, बोर्डिंग ऑपरेशंस, फायरिंग अभ्यास, विध्वंस और विस्फोटक प्रबंधन, असममित युद्ध रणनीति और विशेष हेली-बोर्न ऑपरेशन अभ्यास शामिल थे।

माले पहुँचने पर, भारतीय नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी से मुलाकात की। इस दौरान हुई चर्चाओं में मुख्य रूप से क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का मिलकर सामना करने, प्रशिक्षण भागीदारी को बढ़ाने, नशीले पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध सहयोग को मजबूत करने और चल रही रक्षा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सूचना साझाकरण को और उन्नत बनाने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श हुआ। इसके अतिरिक्त, 15 दिसंबर 2025 को माले में आईएनएस शारदा पर आयोजित एक समारोह में, डीसीएनएस ने मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी को एमएनडीएफ कोस्ट गार्ड शिप हुरावी के लिए ऑपरेशनल स्पेयर पार्ट्स की एक खेप भी सौंपी।

भारतीय नौसेना उप प्रमुख की मालदीव की यह पहली यात्रा, क्षेत्रीय साझेदारों के प्रति भारतीय नौसेना की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। यह दौरा भारत के 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति और क्षेत्र में 'सुरक्षा और विकास के लिए आपसी और समग्र उन्नति' (महासागर) के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत और मालदीव के बीच मजबूत रक्षा और समुद्री सहयोग को रेखांकित करता है।

खाकी पर गंभीर आरोप: युवक ने थाना प्रभारी व दो सिपाहियों पर रुपए छिनने का लगाया आरोप

पीड़ित के विरुद्ध एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज, उच्चाधिकारियों से न्याय की गुहार

खखरेरू / फतेहपुर जनपद फतेहपुर हाल ही में आईजीआरएस निस्तारण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है, लेकिन इसी बीच खखरेरू थाना क्षेत्र से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है।

थाना क्षेत्र के जहांगीर नगर गहुरा निवासी आसिफ पुत्र सफीक अहमद ने खखरेरू थाना प्रभारी सहित दो सिपाहियों पर ₹28,000 नकद एवं ईंट भट्ठे के हिसाब की डायरी जबरन छीनने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत आईजी जोन प्रयागराज एवं पुलिस अधीक्षक फतेहपुर को लिखित तहरीर देकर की है।

आसिफ के अनुसार, 4 दिसंबर को वह अपने ईंट भट्ठे पर ईंटों की बिक्री कर रहा था, तभी खखरेरू थाने से दो सिपाही—जिनके नाम अजीत सिंह एवं दीपक बताए गए हैं—भट्ठे पर पहुंचे और थाना प्रभारी द्वारा बुलाने की बात कहकर उसे थाने चलने को कहा।

युवक ने बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल से थाने के लिए रवाना हुआ, इसी दौरान एक सिपाही उसकी बाइक पर पीछे बैठ गया। जब वे डुडिया पुर गांव के समीप पहुंचे तो पीछे बैठे सिपाही ने उसकी जेब से ₹28,000 नकद एवं बिक्री का हिसाब लिखी डायरी निकाल ली। विरोध करने पर उसे धमकाते हुए थाने ले जाया गया।

एससी/एसटी एक्ट में मुकदमे का विवाद

सूचना मिलने पर युवक के दोनों भाई थाने पहुंचे और थाना प्रभारी से जानकारी मांगी। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक के विरुद्ध गांव के मुकेश पुत्र शिवलाल द्वारा एससी/एसटी एक्ट की तहरीर दी गई है।

पीड़ित के अनुसार, जब कथित शिकायतकर्ता के पिता शिवलाल को थाने बुलाया गया तो उन्होंने किसी भी प्रकार की तहरीर देने से इनकार किया और सीसीटीवी जांच की मांग की। इसके बाद पुलिस ने दबाव बनाकर युवक से झूठा प्रार्थना पत्र लेकर एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया तथा युवक का 151 में चालान कर एसडीएम न्यायालय भेज दिया।

उच्चाधिकारियों से गुहार

पीड़ित युवक ने आईजी जोन प्रयागराज के समक्ष पेश होकर

झूठे एससी/एसटी मुकदमे की जांच,

छिने गए ₹28,000 व हिसाब की डायरी की बरामदगी,

एवं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है।

इस मामले में थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि युवक के आरोप मनगढ़ंत है एससी एसटी एक्ट का मुकदमा पंजीकृत होने के कारण युवक अनर्गल आरोप लगा रहा है ।

अन्ना मवेशियों की समस्या को लेकर किसानों ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

खखरेरू / फतेहपुर नगर पंचायत खखरेरू क्षेत्र में अन्ना मवेशियों की बढ़ती समस्या से परेशान सैकड़ों किसानों ने सोमवार को लोहरपुर चौराहे पर बैठक कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके पश्चात किसान एकजुट होकर नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे, जहां अधिशासी अधिकारी (ईओ) की अनुपस्थिति के चलते किसानों को निराशा का सामना करना पड़ा।

किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा कई बार अधिशासी अधिकारी हरेंद्र सिंह से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। नायब तहसीलदार द्वारा भी ईओ से बात करने की कोशिश की गई, परंतु सफलता नहीं मिली। इससे आक्रोशित किसानों ने अंततः नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की।

किसानों ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र के लोहरपुर, प्रतापपुर, सलवन, सोथरापुर सहित आसपास के गांवों में अन्ना मवेशियों का आतंक पूरी तरह फैला हुआ है। हालात इतने गंभीर हैं कि किसान दिन-रात खेतों की रखवाली करने के बावजूद अपनी फसलों को बचाने में असहाय नजर आ रहे हैं। आवारा गोवंशों द्वारा मटर, चना, लाही एवं गेहूं जैसी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसानों को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष जितेंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में किसानों ने नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए नारेबाजी भी की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही अन्ना मवेशियों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

इस मौके पर अखिलेश सिंह, मनोज सिंह, दिलीप सिंह, सत्येंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, उदयभान सिंह, रोहित कुमार, ज्ञान सिंह, राम अभिलाष मिश्रा सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे

तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने भिड़ंत, एक की मौत, तीन गंभीर घायल

खखरेरू / फतेहपुर थाना क्षेत्र के दरिया मऊ पुलिया के पास सोमवार शाम तेज रफ्तार दो बाइकों के बीच आमने-सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार भदौहा गांव निवासी रमेश कुमार पुत्र जब्बार (उम्र लगभग 40 वर्ष) अपनी पत्नी फूलन देवी एवं पुत्र अंशु के साथ रविवार को अपने साढ़ू के घर किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। सोमवार शाम करीब 5 बजे वह गुरसंडी से अपने गांव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान धाता की ओर से आ रही तेज रफ्तार बाइक से दरिया मऊ पुलिया के पास आमने-सामने टक्कर हो गई।

दुर्घटना में रमेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी फूलन देवी एवं पुत्र अंशु गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी बाइक पर सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जबकि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

इस संबंध में थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने बताया कि मौके पर एक बाइक सवार की मौत हो गई है गंभीर रूप से घायल तीनों लोगों को मंझनपुर इलाज के लिए भेज दिया दिया गया है

देश के सबसे बड़े डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म 'स्पर्श' पर 31.69 लाख रक्षा पेंशनभोगी पंजीकृत हुए

पुराने विवादों के 94.3 प्रतिशत मामले सुलझा लिए गए; शिकायतों के निवारण का औसत समय 56 दिनों से घटकर 17 दिन हो गया

(एजेंसी)।

सही समय पर सही पेंशनभोगी को सही पेंशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेंशन प्रशासन प्रणाली - रक्षा (स्पर्श), जो डिजिटल इंडिया की एक प्रमुख पहल है, देश का पहला संपूर्ण डिजिटल पेंशन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। प्रयागराज स्थित पीसीडीए (पेंशन) के माध्यम से रक्षा लेखा विभाग (डीएडी) द्वारा संचालित 'स्पर्श' ने नवंबर, 2025 तक भारत और नेपाल में 31.69 लाख रक्षा पेंशनभोगियों को अपने साथ जोड़ा है। यह 45 हजार से अधिक एजेंसियों द्वारा पहले प्रबंधित खंडित प्रणाली को एक एकीकृत, पारदर्शी और जवाबदेह डिजिटल ढांचे से प्रतिस्थापित करता है।

प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं: पुराने सिस्टम से संबंधित 94.3 प्रतिशत विसंगतिपूर्ण मामलों का समाधान हो गया है : पिछली प्रणाली से स्थानांतरित किए गए 6.43 लाख विसंगतिपूर्ण मामलों में से 6.07 लाख मामलों को पेंशनभोगियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना सामान्य कर दिया गया है।

बुजुर्गों और तकनीकी रूप से कम जानकार पेंशनभोगियों के लिए व्यापक पहुंच : देश में 284 'स्पर्श' पहुंच कार्यक्रम और 194 रक्षा पेंशन समाधान कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष में आयोजित इन कार्यक्रमों के दौरान 8 हजार से अधिक शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।

बढ़ी हुई पारदर्शिता और शिकायत निवारण : पेंशनभोगी अब अपनी पेंशन की पूरी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं और आसानी से सुधार संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायतों के निवारण का औसत समय अप्रैल, 2025 में 56 दिन से घटकर नवंबर, 2025 में 17 दिन हो गया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रक्षा लेखा विभाग ने 73 प्रतिशत संतुष्टि अंक प्राप्त किया है जिससे यह मंत्रालयों/विभागों में 5 वें स्थान पर है।

डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र 4.0 अभियान : रक्षा एवं पेंशनभोगी विभाग (डीओपी एंड पीडब्ल्यू) के राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डीएलसी) 4.0 अभियान (1-30 नवंबर, 2025) के अंतर्गत रक्षा लेखा विभाग ने 202 कार्यालयों, 4.63 लाख सामान्य सेवा केंद्रों और 15 भागीदार बैंकों को सक्रिय किया है जिन्हें 27 नोडल अधिकारियों का सहयोग प्राप्त है। 30 नवंबर, 2025 तक रक्षा पेंशनभोगियों के लिए 20.94 लाख डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं, जो सभी विभागों में सबसे अधिक है।

वितरण : वित्त वर्ष 2024-25 में, रक्षा पेंशन बजट के अंतर्गत 1,57,681 करोड़ रुपये का वितरण 'स्पर्श' के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर किया गया। जुलाई, 2024 में लागू वन रैंक वन पेंशन-III के अंतर्गत मात्र 15 दिनों में 20.17 लाख लाभार्थियों को 1,224.76 करोड़ रुपये का त्वरित वितरण संभव हुआ।

'स्पर्श' देश की सबसे बड़ी एकीकृत पेंशन प्रणाली है और रक्षा कर्मियों के लिए एकमात्र पूर्णतः एकीकृत डिजिटल पेंशन समाधान है। यह पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सम्मान, देखभाल और समय पर सहायता सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारतीय रेल ने उर्वरक लोडिंग में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जिससे देश भर के किसानों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हुई है

चालू वित्त वर्ष में अब तक भारतीय रेल ने 17,168 उर्वरक रैक लोड किए हैं, जिससे ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिली है

(एजेंसी)।

भारतीय रेल भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पूरे देश में उर्वरकों की सुचारू और समय पर आवाजाही सुनिश्चित करता है। इस वर्ष 30 नवंबर तक उर्वरक की लोडिंग 17,168 रेक तक पहुंच गई। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के 15,369 रेक की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि है। यह वृद्धि रेलवे नेटवर्क के कुशल संचालन को दर्शाती है।

कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। किसानों को बुवाई के लिए समय पर उर्वरकों की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेल ने उर्वरक और खाद्यान्न ले जाने वाली ट्रेनों को प्राथमिकता दी है। इससे देश भर के राज्यों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

आवश्यक माल ढुलाई सेवाओं को मजबूत करके रेलवे लाखों किसानों की मदद कर रहा है। यह ग्रामीण आजीविका, खाद्य सुरक्षा और समग्र आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा दे रहा है। यह प्रदर्शन भारतीय रेल की राष्ट्र निर्माण के प्रति संकल्प और भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला को समर्थन देने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है।

भारतीय रेल विश्वसनीय, व्यापक और कुशल परिवहन प्रदान करके पूरे देश में उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उर्वरक रैकों की प्राथमिकता के आधार पर आवाजाही करके, रेलवे किसानों को निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने में मदद करता है, जिससे वे बिना किसी देरी के कृषि कार्य कर सकें।

रक्षा मंत्री रक्षा संपदा दिवस समारोह में शामिल होंगे; विभाग ने अपने 100वें वर्ष में प्रवेश किया

(एजेंसी)।

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 16 दिसंबर, 2025 को दिल्ली छावनी स्थित रक्षा संपदा भवन में रक्षा संपदा दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर वे देश भर में फैले 61 छावनी बोर्डों के रक्षा भूमि प्रबंधन और नगर प्रशासन के क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार प्रदान करेंगे।

इस वर्ष के समारोह का विशेष महत्व है, क्योंकि विभाग अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जो उस विरासत का स्मरणोत्सव है जिसकी शुरूआत 1765 में हुई थी, जब पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में पहली छावनी स्थापित की गई थी। इसके बाद डेढ़ शताब्दी में दानापुर (1766), मेरठ (1803), अंबाला (1843), दिल्ली (1915) आदि जैसी छावनियों की स्थापना हुई, जिन्होंने भारत में रक्षा और भूमि प्रशासन की नींव रखी। बाद में 16 दिसंबर, 1926 को रक्षा मंत्रालय के अधीन भूमि और छावनी विभाग के रूप में इस विभाग को औपचारिक रूप दिया गया।

रक्षा संपदा विभाग आज रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार की सबसे बड़ी भू-संपत्ति का प्रबंधन करता है। इतिहास में अपनी गहरी जड़े जमाए हुए विभाग ने आधुनिकीकरण की एक असाधारण यात्रा तय की है, जिसने स्वयं को डिजिटल एवं प्रौद्योगिकी-आधारित भूमि प्रबंधन में अग्रणी बना लिया है। विभाग ने छावनी के 20 लाख निवासियों को शत-प्रतिशत नगरपालिका सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराकर ई-छावनी परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है। जल संरक्षण और जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए विभाग के प्रयासों को सर्वोच्च स्तर पर मान्यता मिली है और इसे 'जल संचय जन भागीदारी' के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

विभाग ने पुराने भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटलीकरण कर दिया है, जिससे भविष्य में उनका संरक्षण सुनिश्चित हो सके। संपूर्ण फाइल प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया है और देशव्यापी स्तर पर एक सुरक्षित, प्रौद्योगिकी-समर्थित फाइल प्रबंधन प्रणाली को अपनाया गया है।

लोकतंत्र सेनानी के निधन पर राजकीय सम्मानः पुलिस गारद ने दी अंतिम सलामी, श्रद्धांजलि में जनसैलाब उमड़ा

(एजेंसी)। पीलीभीत

पीलीभीत,घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव सिमरा में एक लोकतंत्र सेनानी के निधन पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को सलामी देने के लिए पुलिस लाइन से गारद बुलाई गई, और अंतिम विदाई में हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस गारद ने पार्थिव शरीर को पूर्ण सैनिक सम्मान के साथ सलामी दी,

लोकतंत्र सेनानी के योगदान को याद करते हुए ग्रामीणों ने "अमर रहें" के नारों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। जिसमें बंदूकों की सलामी और राष्ट्रगान भी शामिल था। यह सम्मान उनके देशसेवा और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक था।

अंतिम यात्रा में परिवारजन, पड़ोसी गांवों के लोग और स्थानीय नेता शामिल हुए। एक ग्रामीण ने कहा, "उनकी कमी हमेशा खलेगी, लेकिन उनका संघर्ष हमें प्रेरित करता रहेगा।" इस घटना ने क्षेत्र में लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को फिर से रेखांकित किया।

सरस्वती शिशु मंदिर में मातृ सम्मेलनः महिला सशक्तिकरण व सुरक्षा पर दिया संदेश

(एजेंसी)। पीलीभीत

पीलीभीत,जोगराजपुर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सप्त शक्ति संगम/मातृ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान व सामाजिक एकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया, और वक्ताओं ने नारी को समाज की आधारशिला बताते हुए स्वावलंबन व सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम की मुख्य वक्ता सूर्यवाला शर्मा ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा व जागरूकता की आवश्यकता बताई, जबकि मुख्य अतिथि ममता शर्मा और विशिष्ट अतिथि सोनी त्रिवेदी ने नारी सम्मान व एकता पर बल दिया। सेहरामऊ उत्तरी थाने की महिला सुरक्षा टीम ने भी हिस्सा लिया, जहां महिला आरक्षी

सपना पाल व सुमन यादव ने महिलाओं को सुरक्षा योजनाओं, हेल्पलाइन नंबरों व कानूनी अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसी जागरूकता से महिलाएं प्रताड़ना से बच सकेंगी।

इस अवसर पर जन शिक्षा समिति पीलीभीत के जिलाध्यक्ष हरिओम अवस्थी, सुभाष त्रिवेदी, सुभाष मिश्रा, शिवकुमार, मुकेश तिवारी, अंशू, शोभित दीक्षित, गौरव गुप्ता व श्याम बिहारी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य आदेश कुमार त्रिवेदी ने आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। सम्मेलन मातृ शक्ति

धान क्रय केंद्रों पर फर्जी खरीद का काला खेलः कागजों में धान बिका, जमीन पर सन्नाटा

(एजेंसी)। पीलीभीत

पीलीभीत,धान क्रय केंद्रों पर भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है, जहां कागजों पर धान की खरीद दर्ज की जा रही, लेकिन वास्तविकता में केंद्रों पर सन्नाटा छाया है। किसानों को धान लाए बिना ही दस्तावेजों पर अंगूठे लगवाकर फर्जी एंट्री की जा रही, और सरकारी खरीद प्रक्रिया को निजी कमाई का हथियार बना दिया गया। मंडी सचिव, मार्केटिंग अधिकारी (एमओ) व क्रय केंद्र प्रभारियों की कथित सांठगांठ से राईस मिलर्स को खुली छूट मिली हुई, जिससे लाखों रुपये के फर्जी भुगतान हो रहे। प्रशासन की आंखें बंद होने से यह भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया है।

किसानों ने शिकायत की कि बीसलपुर व अन्य मंडियों के कई केंद्रों पर बिना तोल के ही रिकॉर्ड तैयार कर सरकारी कोटे का दुरुपयोग किया जा रहा। एक प्रभावित किसान ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "हमें धान लाने का बहाना बनाकर अंगूठा लगवाते हैं, लेकिन असल धान मिलर्स के पास चला जाता। हमारा नाम इस्तेमाल कर वे लाखों का भुगतान ले लेते।" इस गोरखधंधे से सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान हो रहा, जबकि असली किसान वंचित रह जाते।

किसान संगठनों ने मंडी सचिव व प्रभारियों पर मिलीभगत का सीधा आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि तत्काल जांच व कार्रवाई न हुई तो जिले भर में बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में ले लिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। किसानों की मांग है कि फर्जी एंट्री की जांच हो और दोषियों को सजा मिले।

इंग्लैंड स्टडी वीजा के नाम पर 9.65 लाख की ठगीः जालसाज ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर युवक को बेवकूफ बनाया

(एजेंसी)। :पीलीभीत

पीलीभीतःजिले में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक जालसाज ने स्टडी वीजा का लालच देकर युवक से 9 लाख 65 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश पर आरोपी के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू हो गई। आरोपी ने शैक्षणिक दस्तावेजों में हेराफेरी की और पैसे लौटाने से इनकार कर धमकी तक दे डाली।

थाना सुनगढ़ी के नौगांव पकड़िया निवासी मोहम्मद अरबाज (पुत्र अकील अहमद) ने बताया कि उसके पारिवारिक संबंध थाना जहानाबाद के

सरदार नगर निवासी फैज मलिक से थे, जो आवास विकास कॉलोनी में विदेश भेजने वाली कंपनी चलाता था। अरबाज ने इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए स्टडी वीजा पर संपर्क किया, तो फैज ने 14 लाख रुपये की मांग की। विश्वास करते हुए अरबाज ने फाइल चार्जिंग व फीस के नाम पर 6 लाख 65 हजार रुपये किस्तों में दे दिए। फैज ने इंटरव्यू भी करवाया और पास होने की बात कहकर अतिरिक्त 2 लाख 50 हजार रुपये (30 अगस्त 2024 को बैंक ट्रांसफर) व 50 हजार और वसूल लिए।

लेकिन वीजा न आने पर जांच करने पर पता चला कि फैज ने अरबाज की मार्कशीट में फजीर्वाड़ा किया। पैसे वापस मांगने पर आरोपी ने इनकार कर दिया और गाली-गलौज के साथ जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित अरबाज ने एसपी से गुहार लगाई, जिसके आदेश पर सदर कोतवाली में धोखाधड़ी, जालसाजी व अन्य धाराओं में फैज मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार ने पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी की तलाश जारी है और पूरे मामले की गहन जांच की जा रही।

यह घटना विदेश भेजने वाली एजेंसियों पर सवाल खड़े कर रही। पीड़ित ने न्याय की उम्मीद जताई।

उप चीनी आयुक्त बरेली ने एल.एच. चीनी मिल पीलीभीत गेट का निरीक्षण किया,सुविधाओं का जायजा लिया।

(एजेंसी)।

पीलीभीत। उप चीनी आयुक्त बरेली किसानों का हाल जानने पीलीभीत पहुंचे।

उप चीनी आयुक्त बरेली ने एल.एच. चीनी मिल पीलीभीत गेट का निरीक्षण किया और वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसान विश्रामालय और कैंटीन का भी निरीक्षण किया।

किसान विश्रामालय में सुविधाएं

- तख्त और गद्दे डाले गए हैं ताकि किसान आराम कर सकें।
- सर्दी से बचाव के लिए रूम हीटर लगाए गए हैं।

कैंटीन की व्यवस्था

- किसानों के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है जहां वे अपनी जरूरतों का सामान पूरा कर सकते हैं।

वाहनों की सुरक्षा

- सभी वाहनों में रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि रात में वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

इस निरीक्षण के दौरान जिला गन्ना अधिकारी पीलीभीत, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पीलीभीत और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। यह निरीक्षण गन्ना किसानों के हितों की रक्षा और उनकी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

पीलीभीतःबिजली विभाग में ईशु मिश्रा बने बिलिंग पर्यवेक्षक, बीसलपुर शहर की जनता को मिली राहत

(एजेंसी)। पीलीभीत

बीसलपुर।

बिजली विभाग में ईशु मिश्रा को बिलिंग पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद बीसलपुर शहर की जनता को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। उनके कार्यभार संभालते ही बिजली बिल से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान शुरू हो गया है, जिससे उपभोक्ताओं में संतोष व्याप्त है।

शहरवासियों का कहना है कि पहले गलत बिल, अधिक बिलिंग, नाम व मीटर संबंधी त्रुटियों को ठीक कराने के लिए विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब ईशु मिश्रा के बिलिंग पर्यवेक्षक बनने के बाद शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। समयबद्ध निस्तारण से आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।

ईशु मिश्रा बिलिंग पर्यवेक्षक बीसलपुर शहर मोबाइल नं. 9410830323

ईशु मिश्रा ने बताया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उनका उद्देश्य है कि किसी भी उपभोक्ता को बेवजह परेशान न होना पड़े और विभाग व जनता के बीच विश्वास का माहौल बने। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि बिलिंग से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए सीधे विभाग से संपर्क करें।

बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी ईशु मिश्रा के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बिलिंग व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और शिकायतों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है।

ईशु मिश्रा की नियुक्ति से बीसलपुर शहर में बिजली विभाग की छवि बेहतर हुई है। जनता ने उम्मीद जताई है कि इसी तरह तत्परता और ईमानदारी से कार्य होते रहे तो भविष्य में बिजली से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह समाप्त हो सकेंगी।

पीलीभीतः समाजवादी छात्रसभा के जिलाध्यक्ष व उपाध्यक्ष नजरबंद–पुलिस कार्रवाई पर सवाल, कार्यकर्ताओं में रोष

(एजेंसी)।

पीलीभीत।

समाजवादी छात्रसभा पीलीभीत के जिलाध्यक्ष अभिषेक गंगवार एवं उपाध्यक्ष दानिश अल्वी को पुलिस प्रशासन द्वारा नजरबंद किए जाने का मामला सामने आया है। छात्रसभा नेताओं का आरोप है कि बिना किसी लिखित आदेश के, मात्र मौखिक सूचना के आधार पर उन्हें रात्रि लगभग 12 बजे से नजरबंद कर दिया गया, जो अब तक जारी है।

समाजवादी छात्रसभा के जिलाध्यक्ष अभिषेक गंगवार ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह अलोकतांत्रिक है और सरकार की तानाशाही मानसिकता को उजागर करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि न तो कोई लिखित आदेश दिखाया गया और न ही नजरबंदी का स्पष्ट कारण बताया गया।

उपाध्यक्ष दानिश अल्वी ने भी पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि समाजवादी छात्रसभा हमेशा से छात्रहित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है।

छात्रसभा नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे समाजवादी आंदोलन के सिपाही हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. अखिलेश यादव के विचारों से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह का दमनात्मक रवैया उन्हें डराने वाला नहीं है, बल्कि संघर्ष को और मजबूती देगा।

इस घटना के बाद समाजवादी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में रोष व्याप्त है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से नजरबंदी तत्काल समाप्त करने तथा लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करने की मांग की है। मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।

माघ मेला 2026 को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के दृष्टिगत मेला सलाहकार समिति की बैठक

(एजेंसी)। प्रयागराज

मेला प्राधिकरण कार्यालय स्थित आईसीसीसी सभागार में संपन्न हुई जिसमें पूज्य संत-महात्माओं, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए। सर्वप्रथम अपर मेला अधिकारी, माघमेला श्री दयानंद प्रसाद एवं पुलिस अधीक्षक माघमेला श्री नीरज कुमार पांडेय ने प्रशासन एवं पुलिस द्वारा की गई व्यवस्थाओं की पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी दी। तत्पश्चात सभी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधियों ने एक एक कर अपनी बात रखी।

इस क्रम में सर्वप्रथम तीर्थ पुरोहितों का प्रतिनिधित्व कर रहे श्री रामबाबू ने श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, सभी सेक्टरों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहे तथा माघ मेले में मोबाइल कनेक्टिविटी भी सुचारू ढंग से चलती रहे यह सुनिश्चित करने की अपील की। नाविक संघ के प्रतिनिधि पप्पू लाल ने जानकारी देते हुए कहा की कुंभ की भीड़ को देखते हुए यहाँ के नाविकों ने माघ मेले के दृष्टिगत काफी भारी तादाद में नावों की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। अतः बाहर की नावों का रजिस्ट्रेशन करने एवं मोटर बोट चलाने से रोका जाना चाहिए। सिविल डिफेंस के चीफ वार्डन श्री अन्नू गुप्ता ने पुलिस बूथ पर तैनात पुलिसकर्मियों को अच्छे से प्रशिक्षण देने के पश्चात ही उनकी तैनाती करने का सुझाव दिया जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं की अधिक से अधिक मदद

की जा सके।

आचार्य बाड़ा के उपस्थित प्रतिनिधि ने अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जहाँ उनकी बसावट की जा रही है वहाँ अभी तक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य सुविधाएं जैसे शौचालयों की संख्या को बढ़ाने की भी अपील की। इसका समर्थन करते हुए श्री कौशलेन्द्र प्रपचार्यजी महाराज ने आचार्य बाड़ा एवं अन्य संस्थाओं की मूलभूत सुविधाएँ बढ़ाने की अपील।

खाक चौक के उपस्थित प्रतिनिधि ने प्रशासन से भूमि आवंटन के समय भूमि के साइज के अनुसार एक नया मानक बनाते हुए कितने बड़े प्लॉट में कितने शौचालयों की आवश्यकता है इसका आकलन कर भविष्य में सुविधाएं देने का सुझाव दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि समय के साथ साधु संन्यासियों की संख्या बढ़ रही है अतः संस्थाओं को अधिक भूमि एवं मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है। श्री लेटे हनुमान जी के महंत श्री बलबीर गिरिजी महाराज ने मेला क्षेत्र में एक बेहतर साइनेज व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया।

सांसद श्री उज्ज्वल रमन सिंह के प्रतिनिधि ने सभी पीपा पुलों को श्रद्धालुओं हेतु खोले रखने एवं उसमें सुचारू ढंग से ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। शहर उत्तरी विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी ने फाफामऊ से शहर आने हेतु बनाए जा रहे दो अतिरिक्त पॉन्टून पुलों को समय के अंतर्गत बनाने, श्रद्धालुओं को किसी भी हाल में घाटों के निकट सोने न देने तथा नागवासुकी के सामने बनाई गई कोस्टल रोड पर स्थायी रूप से बिजली की व्यवस्था करने के सुझाव दिए। महापौर श्री उमेश चंद्रगणेश केसरवानी ने सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा की उचित व्यवस्था करने तथा अधिक भीड़ की संभावना के दृष्टिगत पहले से ही शहर के कुछ स्कूलों में होल्डिंग एरिया की व्यवस्था रखने का सुझाव दिया।

अंत में अपर मेला अधिकारी श्री दयानंद प्रसाद ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी से माघ मेला के आयोजन को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिए सहयोग प्रदान करने की अपील की।

पीलीभीतः सीजीएम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला–किसान नेता गुल्लू पहलवान फर्जी मुकदमे से बरी, समर्थकों में खुशी की लहर

(एजेंसी)।

पीलीभीत/बीसलपुर।

बीसलपुर स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में किसान नेता मोहम्मद साबिर उर्फ गुल्लू पहलवान को फर्जी मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें निर्दोष साबित करते हुए यह फैसला सुनाया, जिससे उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई।

अदालत से बरी होने की खबर मिलते ही रविवार को बड़ी संख्या में समर्थक उनके आवास पर पहुंचे और जोरदार स्वागत किया। फूल-मालाएं पहनाकर, मिठाइयां खिलाकर एक-दूसरे को बधाई दी गई। इस दौरान ढोल-नगाड़ों और नारों के बीच न्याय की जीत का जश्न मनाया गया।

किसान नेता मोहम्मद साबिर उर्फ गुल्लू पहलवान ने बताया कि वर्ष 2007 में बसपा सरकार के दौरान उन पर और उनके साथियों पर कथित रूप से फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए थे। उन्होंने कहा कि वर्षों तक चले इस मुकदमे में उन्हें मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, लेकिन न्यायपालिका पर उन्हें हमेशा भरोसा रहा।

इस पूरे मामले की प्रभावी पैरवी एडवोकेट मनोज कुमार कुशवाहा द्वारा की गई। उनके सफल प्रयासों से अदालत में सच्चाई सामने आई और किसान नेता को न्याय मिला। बरी होने के बाद समर्थकों ने एडवोकेट मनोज कुमार कुशवाहा का भी फूल-मालाओं से स्वागत कर आभार व्यक्त किया।

तराई विकास मंच के जिलाध्यक्ष चंद्रपाल मौर्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुल्लू पहलवान के आवास पहुंचे और इस फैसले को न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला फर्जी मुकदमों के खिलाफ एक मिसाल है और किसानों व जनआंदोलनों से जुड़े लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा बनाए रखने की प्रेरणा देता है।

इस मौके पर अमन कश्यप, गुड्डू, भुट्टा, आनंद, सलमान खान, रविकांत एडवोकेट सहित अनेक कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह फैसला सत्य और न्याय की विजय है।